

आकाशवाणी गोरखपुर  
प्रादेशिक समाचार

दिनांक-02 अगस्त 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला- राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में उपवर्गीकरण का है अधिकार।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा- प्रदेश को एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा बजट।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका की खारिज। कहा- सिविल सूट सुनवाई योग्य।
- माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकाण्ड में पुलिस को मिली क्लीन चिट।

\*\*\*\*\*

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने कल बहुमत से फैसला दिया कि राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दो हजार चार के ईवी चिन्मैया के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप-वर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसा वर्ग नहीं है, जिसमें सबकी एक समान स्थिति हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद चौदह का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद पंद्रह और सोलह किसी राज्य को एक जाति का उप-वर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं।

\*\*\*\*\*

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार चौबीस- पच्चीस के मूल बजट का आकार साढ़े सात लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। यह दो हजार पंद्रह-सोलह के बजट के आकार से दोगुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदेश के बजट का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते फरवरी माह में वित्तीय वर्ष चौबीस- पच्चीस के लिए पारित मूल बजट की चौवालिस प्रतिशत धनराशि जारी हो चुकी है और बीस प्रतिशत खर्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभायेगा।

**हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते ७0प्र० का भी दायित्व बनता था कि हम देश की इस स्पीड के साथ ७0प्र० के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिये ७0प्र० ने भी तय किया कि हम ७0प्र० की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे और एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिये ७0प्र० सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारम्भ किये हैं। ७0प्र० का यह बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है।**

इससे पहले सदन में सपा सदस्यों ने गोरखपुर में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापित करने के लिये तैयार चबूतरे को ध्वस्त करने और किसानों के लिये एमएसपी का मुद्दा उठाया। दोनों मामलों में जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य वेल में आ गये।

उधर, विधान परिषद में पेपर लीक और पुरानी पेंशन का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि प्रदेश में पेपरलीक एक उद्योग बन गया है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शित और शुचिता के साथ निष्पक्ष रूप से नौकरी देने के लिये प्रतिबद्ध है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन का मामला उठाया। जवाब में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति लोक-प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग विधेयक दो हजार चौबीस को प्रवर समिति के सौंप दिया गया। समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

\*\*\*\*\*

केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्रालय ने कल लखनऊ में आम बजट पर चर्चा और स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षुओं का अभिनन्दन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास से संबंधित कोई भी मदद चाहेगा तो मंत्रालय उसे तत्काल स्वीकृति देगा। श्री चौधरी ने कहा कि देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं।

*समन्वयक बनाकर ग्रासरूट तक क्रियान्वयन करके उन चीजों को उन प्रयासों को सार्थक बनाने की आवश्यकता है उसमें जनभागादारी और लोगों को जागरूक करना यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिये जब से मैंने मंत्रालय संभाला है। हमने टीम में बैठक कर हमने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा हम सीधा संवाद करेंगे। जो भी बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखे है कौशल विकास के उसमें एकबार फिर राज्यों की बड़ी भूमिका होनी है और इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप मॉडल में कई राज्यों में अच्छे प्रयोग हुए हैं मैं भी प्रोत्साहित करूंगा। यूपी में भी इस काम को आगे तीव्र गति से बढ़ाये कुछ जगह प्रयोग करे उनसे सीख ले और फिर उसको सेटप कर लो।*

कार्यक्रम में प्रदेश के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अतुल कुमार तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

\*\*\*\*\*

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए उस दलील को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वाद वरशिप एक्ट अन्य प्रावधानों से बाधित है। साथ ही सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि सिविल सूट सुनवाई योग्य है, इस मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए बारह अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई का समय दिया है। हाईकोर्ट अब सभी अट्टारह याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में छः जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

\*\*\*\*\*

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस को क्लीन चिट मिल गयी है। पुलिस अभिरक्षा में हुयी हत्या की जांच के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था। आयोग की रिपोर्ट कल वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पन्द्रह अप्रैल दो हजार तेइस को मोलीलाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पुलिस अधिकारियों के इशारे पर नहीं हुयी थी। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और न ही अभिरक्षा में लापरवाही बरती गयी। रिपोर्ट के अनुसार घटना अचानक नौ सेकेंड में हो गयी थी। इतने कम समय में वहां पुलिसकर्मियों के पास कुछ करने का मौका नहीं था।

\*\*\*\*\*

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुष्प वर्षा कर कल कांवड़ियों का स्वागत किया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा सहित अन्य जनपदों में भी कांवड़ियों का जगह-जगह स्वागत हुआ। मुजफ्फरनगर में गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ दिख रही है। हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट.....

*मुजफ्फरनगर जिला इस समय शिव की भक्ति में लीन है। मुजफ्फरनगर के मार्ग बम बम के जय घोष से गुजायमान है। हजारों लोग यहां कांवड़ शिविरों के माध्यम से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कांवड़ीयों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा से सभी शिव भक्त श्रद्धालु अभी भूत दिखाई दिए। यहां पर इस समय श्रद्धा भक्ति सेवा का अटूट संगम देखने को मिल रहा है। रणवीर सैनी, आकाशवाणी समाचार, मुजफ्फरनगर।*

\*\*\*\*\*

पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की पचास मीटर राइफल थ्री-पोजिशन शूटिंग प्रतियोगिता में कल भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री योगी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक विजय उनके अथक परिश्रम और असाधारण खेल कौशल का प्रतिफल है। यह जीत देश के असंख्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

\*\*\*\*\*